

वन रैंक वन पेंशन (OROP)

प्रलिस के लयः

[वन रैंक वन पेंशन \(OROP\) योजना, सर्वोच्च नयायालय](#)

मेन्स के लयः

OROP की मुख्य वशिषताएँ, OROP से संबन्धति चुनौतयिँ और इसके नहितिारथ

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में प्रधानमन्त्री ने [वन रैंक वन पेंशन \(OROP\) योजना](#) के कारयान्वयन की सराहना की । इस योजना को आधिकारिक तौर पर 7 नवंबर 2015 को लागू कया गया था, जसिमें प्राप्त लाभों को 1 जुलाई 2014 से प्रभावी बनाया गया ।

- OROP का उद्देश्य सशस्त्र बलों के कार्मिकों को उनके पद एवं सेवा अवधके आधार पर एक समान पेंशन लाभ प्रदान करना है, जो सेवानवृत्त सैनिकों तथा उनके परिवारों के प्रतसरकार की प्रतबिद्धता का प्रतीक है ।

OROP क्या है?

- पृष्ठभूमि:**
 - केपी सहि देव समति(1984) ने [सर्वोच्च नयायालय](#) एवं [उच्च नयायालय](#) के नयायाधीशों हेतु स्थापति पेंशन सदिधांतों के आधार पर 'वन रैंक वन पेंशन' की सफारशि की थी ।
 - चौथे केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन को समान बनाना चुनौतीपूर्ण बताने के साथ इसके लयि बड़े प्रशासनिक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ।
 - पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने 'वन रैंक वन पेंशन' का वरिोध करते हुए तर्क दया कपिद की भूमिका एवं योग्यता में परविरतन के कारण पेंशनभोगयिँ को अतरिकित लाभ नहीं मलिना चाहयि ।
 - कैबनेट सचवि समति(2009) ने 'वन रैंक वन पेंशन' को अस्वीकार कर दया लेकनि सेवानवृत्त लोगों के बीच पेंशन असमानता को कम करने के उपाय सुझाए ।
 - राज्यसभा याचिका समति ने सभी सैन्य बल कार्मिकों हेतु 'वन रैंक वन पेंशन' लागू करने की सफारशि की ।
- परभाषा:** OROP यह सुनश्चिति करता है कएक ही रैंक पर सेवानवृत्त होने वाले सभी सशस्त्र बलों के कार्मिकों को उनकी सेवानवृत्त तिथि की परवाह कयि बना समान पेंशन मलि । उदाहरण के लयि, वर्ष 1980 में सेवानवृत्त होने वाले जनरल को वर्ष 2015 में सेवानवृत्त होने वाले जनरल के समान पेंशन मलिगी ।
 - OROP, समान पेंशन वतिरण के लयि पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधति करता है, तथा राष्ट्र के प्रतउनके बलदान और सेवा को मान्यता देता है ।
- OROP की मुख्य वशिषताएँ:**
 - पेंशन का नरिधारण रैंक और सेवा की अवधके आधार पर कया जाता है, जसिसे सेवानवृत्त लोगों के बीच नषिपक्षता सुनश्चिति होती है, साथ ही उन लोगों को भी सुरक्षा मलिती है जो पहले से ही औसत से अधिक राशि प्राप्त कर रहे हैं ।
 - पेंशन संशोधन: सेवारत कार्मिकों के वेतन और पेंशन में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पाँच वर्ष में पेंशन का पुनर्रिधारण कया जाएगा । पहला संशोधन 1 जुलाई 2019 को हुआ था ।
 - वतितीय नहितिारथ: OROP संशोधनों को लागू करने की अनुमानति लागत लगभग 8,450 करोड रुपए प्रतविरष है ।
 - लाभारथी: इस योजना से 25.13 लाख से अधिक सशस्त्र बल पेंशनभोगी और उनके परिवार लाभान्वति होंगे ।
 - इसमें पारवारिक पेंशनभोगयिँ, युद्ध वधिवाओं और वकिलांग पेंशनभोगयिँ के लयि प्रावधान शामिल हैं ।
 - उत्तर प्रदेश और पंजाब में OROP लाभारथीयिँ की संख्या सबसे अधिक है ।
- OROP पर सर्वोच्च नयायालय का फैसला:**

- [OROP](#) योजना की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की तथा यह नरिधारित किया कि एक ही रैंक के कार्मिकों के लिये उनकी सेवानवृत्त तिथि के आधार पर अलग-अलग पेंशन देना मनमाना नहीं है।
 - इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पेंशन में अंतर वभिन्न कारकों जैसे संशोधित सुनश्चिति कैरियर प्रगति (MACP) और आधार वेतन गणना से उत्पन्न होता है।



OROP के सामाजिक-आर्थिक नहितार्थ क्या हैं?

- **कल्याण संवर्धन:** OROP से दगिगजों और उनके परिवारों की वत्तितय सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होता है, तथा उनके समग्र कल्याण में योगदान मलित है।
- **आर्थिक प्रभाव:** पेंशन में वृद्धि से दगिगजों की प्रयोज्य आय में वृद्धि हो सकती है, जससे व्यय में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मलिया।
- **सामाजिक मान्यता:** OROP का कार्यानवयन सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा किये गए बलदिन की सार्वजनिक स्वीकृति के रूप में कार्य करता है, तथा समाज में गौरव और सममान की भावना को बढ़ावा देता है।
- **एक समान पेंशन:** यह समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक से सेवानवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिये समान पेंशन सुनश्चिति करता है, चाहे उनकी सेवानवृत्त तिथि कुछ भी हो।
- वर्तमान मानकों के अनुरूप पेंशन का नरिधारण हर पाँच वर्ष में पुनः किया जाता है।




10

years of

OROP

A Milestone for Empowering Ex-Servicemen

Total OROP-III Beneficiaries- 21.56 lakhs

Total Rs 1,24,000 Cr additional funds expended since 2014 on account of OROP

| | OROP -I Wef 1.7.2014 | OROP -I Wef 1.7.2014 | OROP-III Wef 1.7.2024 |
|--|-------------------------|--|---|
| No of Armed Forces Pensioners/family pensioners Beneficiaries. | 20.60 Lakh | 25 Lakh (includes 4.52 lakh New Retirees from 1.7.2014- 30.06.2019) | 21.56 Lakh (includes 3.54 lakh New Retirees from 1.7.2019- 30.06.2024) |
| Average annual expenditure | Around Rs 12,000 Crore | | |

| OROP Phases | Beneficiaries | Average Annual Expenditure | Total Service pensioners exp | Total family Pensioners exp |
|-------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| OROP-I | Around 25.14 lakh | Around Rs 12,000 Crore | 82203.08 | 10046.82 |
| OROP-II | | | 23953 | 7368.98 |
| OROP-III | | | 1076.51 | 325.95 |
| | | | 82203.08 | 10046.82 |
| Grand Total | | | 1,24,974.34 | |

(All Amount in Rs Crore)

[@SpokespersonMoD](#)
[@DefenceMinIndia](#)
[MinistryofDefenceGovernmentofIndia](#)

OROP योजना के कार्यान्वयन में क्या मुद्दे हैं?

- **उच्च लागत:** कार्यान्वयन लागत प्रारंभिक अनुमान से काफी अधिक है, जिससे राजकोष पर असर पड़ता है।
 - उदाहरण: प्रारंभ में अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए थी, परंतु वास्तविक लागत 8000-10000 करोड़ रुपए के बीच है।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ:** पात्र कार्मिकों के पछिले रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने और सत्यापित करने में कठिनाइयाँ।
 - उदाहरण: सटीक लाभ प्रदान करने के लिये ऐतिहासिक सेवा रिकॉर्ड तक पहुँच और उसमें आने वाली चुनौतियाँ।
- **जटिल कार्यान्वयन:** योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयित करने में प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी जटिलताएँ।
 - उदाहरण: सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन लाभ की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने में कानूनी और तार्किक मुद्दे।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत के सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण पर वन रैंक वन पेंशन योजना के प्रभाव का आकलन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?]

प्रश्न. NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित “कृषक कुटुम्बों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण” के अनुसार नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2018)

1. राजस्थान में ग्रामीण कुटुम्बों में कृषि कुटुम्बों का प्रतशित सर्वाधिक है।

2. देश के कुल कृषिकुटुम्बों में 60 प्रतिशत से कुछ अधिक ओबीसी के हैं।

3. केरल में 60 प्रतिशत से कुछ अधिक कृषिकुटुम्बों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषिस्रोतों से प्राप्त की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न: किसी दिये गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि (2019)

- (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।
- (b) कीमत स्तर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
- (c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
- (d) सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

उत्तर: (b)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/one-rank-one-pension-orop->

